

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक  
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,  
देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 24 जनवरी, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, विकासनगर (देहरादून) के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या:-67/XVII(3)/09-09(47)/09 दिनांक 26 फरवरी, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, विकासनगर (देहरादून) के निर्माण हेतु ₹ 58.41 लाख के संस्तुत आंगणन के सापेक्ष ₹ 05.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस संबंध में आपके पत्रांक संख्या-4003/सै.क./सै.वि.गृ./विकासनगर दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, विकासनगर (देहरादून) की द्वितीय किश्त हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये कुल ₹ 53.41 लाख (₹ तिरपन लाख एकतालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।
4. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से जी गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।



5. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना की स्वीकृति नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
7. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
9. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ आवश्यक रूप से करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।
10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाए तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
12. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।
13. कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी०पी० डब्लू० फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 के आयाजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम-03-सैनिक कल्याण, 0301-सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
15. उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनोदश संख्या-209/XVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)  
प्रमुखसचिव।